नहीं हो। सरकार वर्कशाप, सेमीनार, विचारविमर्श और साहित्य तथा राज्य स्तर की नोडल एजेंसियों, लघु उद्योग सेवा संस्थाओं और खाद्य प्रसंस्करण परीक्षण केन्द्रों की मार्फत लागत प्रभावी/कम लागत की प्रौद्योगिकी का भी प्रसार कर रही है।

Pending applications from multinationals for investment in food processing sector

3875. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to answer to unstarred Question 5628 given in the Rajya Sabha on 4th May, 1994 and state:

(a) whether any applications from multinationals for investment in food processing industry are lying pending with the Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when these applications are likely to be cleared?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) While decision on the foreign investment has already been taken, action on all the other recent investment proposals by foreign companies has been initiated.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन

3876. श्री राम जेठमलानी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक श्रमप्रधान उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस उद्योग में 15 लाख लोग कार्यरत हैं जो कुल श्रमशक्ति का 19 प्रतिशत हैं जबकि देश के कुल औद्योगिक पूंजी निवेश की मात्र 7.1 प्रतिशत पूंजी ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगी है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने देश की बड़ी कम्पनियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेकों प्रोत्साहन देने की पेशकश करके इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि सरकार के इस कदम से देश में रोजगार के कम अवसर पैदा होने की संभावना के साथसाथ लघु उद्योगों के व्यापारिक हितों पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की स्थिति उत्पन्न होगी; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जी हां।

(ख) और (ग) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1989-90 के अनुसार फैक्ट्री सेक्टर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जिनमें देश के कुल औद्योगिक पूंजी निवेश का 8.1% निवेश निहित है, में 16.02 लाख लोग कार्यरत हैं जो कुल जनशक्ति का 19.7% हैं। असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्थित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं।

(घ) उदारीकृत नीति के अन्तर्गत सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित उद्योग के विभिन्न सेक्टरों में बड़ी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश का स्वागत करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध प्रोत्साहन सभी क्षेत्रों में लागू हैं और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर ऋण देने के अलावा 30 लाख रुपये तक उत्पादन पर उत्पाद शुल्क की छूट के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) कृषि आधारित कच्चे माल की बहुतायत मात्रा में प्रसंस्करण के लिए बड़ी क्षमताएं सृजित करने, अच्छी प्रौद्योगिकी लाने, क्वालिटी बढ़ाने, बाजार विस्तार, निर्यात बढ़ाने, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण, विपणन आदि जैसे अनुषंगी और संबद्ध क्षेत्रों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने के लिए बड़ी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों द्वारा पूंजीनिवेश की आवश्यकता होती है। खाद्य उत्पादों की कुछ मदें लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित हैं।

Downgrading the deep sea fishing

3877. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the Minister of FOOD

PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have made an internal decision to downgrade the importance of marine and deep-sea fisheries;

(b) whether it is a fact that there is no JointSecretary level officer dealing exclusively with the development of deep-sea fisheries.

(c) what are the reasons for down grading deep sea fisheries; and

(d) whether any effort has been made to focus on the finding solution to the industry which is critical to Northern Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Schemes for setting up of cold chain, scheme on tuna and other fish processing, assistance for diversified fishing, scheme for providing interest subsidy on loan for acquisition of deep sea fishing vessels, are being implemented under the 8th Fiveyear Plan for assistance the entrepreneurs, including those from Northern Andhra Pradesh.

Marine Ecology

3878. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Food Processing is allowing multinational companies to come in unhindered into the fishing grounds in Bay of Bengal;

(b) what will be the fate of fishermen and small entrepreneurs based in Andhra Pradesh;

(c) whether such a move will harm marine ecology; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) No multinational company has been allowed for deep sea fishing in the Indian Exclusive Economic Zone. However, a number of Indian Companies have been permitted to set up joint venture companies in collaboration with foreign fishing companies for deep sea fishing in Indian waters by acquisition of vessels through purchase/lease. Operation of such vessels is allowed only beyond the territorial waters, which are reserved for traditional fishermen. At present, only 17 deep sea fishing vessels are in operation under Joint Venture/Lease in the Indian EEZ.

(b) to (d) Do not arise.

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्राप्त हुई पेशकश

3879. श्री राम जेठमलानी: क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग के एकक स्थापित करने हेतु सरकार को अगस्त, 1994 से जून, 1994 की अवधि के दौरान अनेकों पेशकश प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पेशकशों की संख्या कुल कितनी है और इनमें कुल कितना पूंजी निवेश होने की संभावना है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन एककों को शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्थापित करने का निश्चय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले एककों की अलग-अलग संख्या कितनी है तथा इन एककों में अनुमानत: कितने-कितने स्थानीय लोगों को एकक-वार रोजगार प्राप्त को होने की संभावना है; और

(ङ) देश में विभिन्न राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले इन प्रस्तावित एककों की अलग-अलग संख्या कितनी है और मार्च, 1994 तक कुल कितने एकक स्थापित किए जा चुके हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) से (ङ) अगस्त 1991 से जून 1994 तक सरकार को 34,469 करोड़ रु. के प्रस्तावित निवेश वाले 2680 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें 4.82 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रस्ताव है। सरकार ने लगभग 7060 करोड़ रु. के निवेश वाले विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश, निर्यातोन्मुखी यूनिटों और औद्योगिक लाइसेंस संबंधी परियोजना प्रस्तावों